RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 313
दि. 17.03.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

राज्य में घरेलू तथा वाणिज्यिक पीएनजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के बफर स्टॉक में लगातार वृद्धि

- राज्य में एलपीजी सहित केरोसिन वितरण संबंधी व्यवस्था भी की जा रही है : सुश्री मोना खंधार, अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
- एलपीजी संबंधी किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन के लिए राज्य हेल्पलाइन से संपर्क किया जा सकता है
- निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सभी गैस एजेंसियों की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की टीम तैनात

(जीएनएस)। गांधीनगर : राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष 2026-27 के बजट अंतर्गत सोमवार को गांधीनगर स्थित विधानसभा परिसर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से संवाददाता संमेलन का आयोजन किया गया। इसमें खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता सुरक्षा मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता सुरक्षा राज्य मंत्री श्री पी. सी. बरंडा उपस्थित रहे। मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी ने विभाग के उद्देश्य 'अंत्योदय से सर्वोदय, सबको अन्न, सबको पोषण' के मंत्र के साथ सुदूरवर्ती-दूरदराजी व्यक्ति की खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकार के विजन की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

इस संवाददाता संमेलन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलों के विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री मोना खंधार ने एलपीजी की आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं पर स्पष्टता करते हुए कहा कि राज्य में

नागरिकों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर का पर्याप्त भंडार है और बफर स्टॉक में भी लगातार वृद्धि हो रही है। केन्द्र सरकार के साथ निरंतर समन्वय में रहते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। राज्य में घरेलू तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिए पीएनजी का भी पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी उपभोक्ताओं में कन्वर्ट करने को प्राथमिकता

सुश्री मोना खंधार के अनुसार हाल में एलपीजी के घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पीएनजी उपभोक्ताओं में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है। जिन उपभोक्ताओं के पास एलपीजी के साथ पीएनजी कनेक्शन भी हैं, उन्हें बुधवार तक एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने होंगे।

हर जिले में 36 हजार लीटर केरोसिन का आवंटन

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी आपूर्ति के साथ-साथ अतिरिक्त विकल्प के रूप में केरोसिन के वितरण की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है। सुश्री खंधार के अनुसार केरोसिन का यह भंडार एलपीजी के उपरांत उपलब्ध कराया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा 1452 किलोलीटर (1452000 लीटर) केरोसिन का भंडार आवंटित किया गया है। इसमें हर जिले को 36 हजार लीटर केरोसिन का आवंटन किया गया है, जिसमें प्रति परिवार 5 लीटर तथा प्रति संस्था 25 लीटर केरोसिन का आवंटन शामिल है। इसके लिए जरूरी व्यवस्था की जा रही है।

आवश्यक तथा अर्धावश्यक सेवाओं के अनुसार एलपीजी का आवंटन

राज्य में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों में 100 प्रतिशत, जबकि फार्मा, डेयरी उद्योग, सीड प्रोसेस इंडस्ट्री, एयरलाइन/रेलवे कैंटीन में 70 प्रतिशत तथा मत्स्योद्योग जैसी आवश्यक सेवाओं में 10 प्रतिशत कैप के साथ वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा रेस्टोरेंट/ढाबे, होटल, कॉर्पोरेट कैंटीन, औद्योगिक कैंटीन, कॉर्पोरेट गेस्ट हाउस तथा फूड प्रोसेसिंग जैसी अर्धावश्यक सेवाओं में 10 कैप के साथ आपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त कदम उठाए गए हैं, जिससे आवश्यकतानुसार सभी क्षेत्रों को जरूरी आपूर्ति उपलब्ध हो।

एलपीजी वितरण की कड़ी देखरेख के लिए अधिकारियों की नियुक्ति

राज्य की सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तथा निजी गैस एजेंसियों में कड़ी देखरेख तथा मॉनिटरिंग के लिए राजस्व एवं पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नागरिकों को समय पर एलपीजी आपूर्ति मिले और अनियमितता रोकी जा सके। पिछले 12 दिनों में जिला स्तर पर 912 तथा राज्य स्तरीय टीम द्वारा 17 मामलों में जाँच कार्य किया गया है।

एलपीजी के लिए राज्य हेल्पलाइन नंबर 1800-232-0222

राज्य में एलपीजी संबंधी किसी भी समस्या के लिए नागरिकों से राज्य हेल्पलाइन नंबर 1800-232-0222 पर संपर्क करने को कहा गया है।

विमान हादसों की गुत्थी सुलझाने में तेजी, बारामती अहमदाबाद दुर्घटनाओं की जांच पर केंद्र की नजर

(जीएनएस)। देश में हाल ही में हुए विमान हादसों को लेकर केंद्र सरकार ने जांच प्रक्रिया को तेज कर दिया है। महाराष्ट्र के बारामती और गुजरात के अहमदाबाद में हुई दो अलग-अलग विमान दुर्घटनाओं की सच्चाई सामने लाने के लिए विशेषज्ञ एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन घटनाओं की जांच अंतरराष्ट्रीय मानकों और निर्धारित तकनीकी प्रक्रियाओं के तहत की जा रही है, ताकि हादसों के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए Manoj Jha ने सरकार से इन दुर्घटनाओं की जांच की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री K. Ram Mohan Naidu ने बताया कि दोनों हादसों की जांच पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ की जा रही है। उन्होंने कहा कि बारामती विमान हादसे की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच विशेष रूप से Aircraft Accident Investigation Bureau (एएआईबी) को सौंपी गई है, जो देश में विमान दुर्घटनाओं की जांच के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है।

मंत्री ने यह भी बताया कि एएआईबी केवल बारामती दुर्घटना ही नहीं बल्कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की भी समानांतर जांच कर रहा है। दोनों मामलों में विशेषज्ञों की टीम तकनीकी पहलुओं, विमान की स्थिति, उड़ान से जुड़ी परिस्थितियों और पायलट की भूमिका जैसे सभी पहलुओं की विस्तार से पड़ताल कर रही है। जांच का उद्देश्य केवल हादसे का कारण ढूंढ़ना नहीं बल्कि उन सभी संभावित जोखिमों की पहचान करना भी है, जो भविष्य में विमानन सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकते हैं।

सरकार के अनुसार बारामती हादसे को लेकर शुरुआती जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इसे संबंधित एजेंसियों को सौंप दिया गया है। हालांकि इस प्राथमिक रिपोर्ट में केवल प्रारंभिक तथ्यों को शामिल किया गया है। दुर्घटना की असली वजह, तकनीकी खामियां या मानवीय भूल जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का खुलासा विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने संसद को बताया कि जांच प्रक्रिया अभी जारी है और अंतिम रिपोर्ट आने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि विमान दुर्घटनाओं की जांच बेहद जटिल होती है। इसमें विमान के ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा, पायलट के संवाद, मौसम की स्थिति और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़े रिकॉर्ड सहित कई तकनीकी पहलुओं का गहन विश्लेषण किया जाता है।

इस मुद्दे को उठाते हुए सांसद मनोज झा ने यह भी कहा था कि पायलट संगठनों ने इन दोनों हादसों की जांच को लेकर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि जांच पूरी तरह निर्धारित और मानक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए, ताकि किसी भी तकनीकी पहलू को नजरअंदाज न किया जाए। पायलट संगठनों का मानना है कि कई बार दुर्घटनाओं की जांच में छोटे-छोटे तकनीकी संकेत भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होते हैं, इसलिए पूरी प्रक्रिया को अत्यंत सावधानी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए।

सरकार ने संसद में इस पर जवाब देते हुए भरोसा दिलाया कि जांच पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त संसाधन, तकनीकी उपकरण और विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। इसके अलावा जांच में अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की चूक की संभावना न रहे।

उन्होंने यह भी कहा कि विमानन सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और हर दुर्घटना को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। किसी भी दुर्घटना से मिले सबक का उपयोग भविष्य में सुरक्षा मानकों को और मजबूत बनाने के लिए किया जाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि विमान दुर्घटनाओं की जांच केवल जिम्मेदारी तय करने के लिए नहीं होती, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना होता है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और भविष्य में इसे कैसे रोका जा सकता है। इसी कारण एएआईबी जैसी एजेंसियां हर तकनीकी पहलू का विस्तार से अध्ययन करती हैं।

फिलहाल बारामती और अहमदाबाद दोनों हादसों की जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि अंतिम रिपोर्ट सामने आने के बाद दुर्घटनाओं के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। इसके साथ ही विमानन क्षेत्र में सुरक्षा से जुड़े नए उपाय और नियम भी सामने आ सकते हैं, जो भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

सेंट जॉर्ज अस्पताल में तीन साल में 521 मौतें, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

(जीएनएस)। मुंबई के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में गिने जाने वाले St. George Hospital में पिछले तीन वर्षों के दौरान आईसीयू में हुई मरीजों की मौतों के आंकड़ों ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार मई 2022 से जुलाई 2025 के बीच अस्पताल के आईसीयू में भर्ती 521 मरीजों की मौत दर्ज की गई। यह जानकारी सामने आने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, डॉक्टरों की उपलब्धता और अस्पताल प्रबंधन को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

इस मामले को लेकर महाराष्ट्र विधान परिषद में चर्चा के दौरान राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री Hasan Mushrif ने सदन को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिए गए समयकाल के दौरान आईसीयू में भर्ती कई गंभीर मरीजों का इलाज किया गया, जिनमें से 521 मरीजों की मौत हुई। इसके साथ ही एक और

चिंताजनक तथ्य सामने आया कि लगभग 7.8 प्रतिशत मरीज अपना इलाज पूरा किए बिना ही अस्पताल से चले गए। विशेषज्ञों का मानना है कि गंभीर हालत में अस्पताल छोड़ने वाले मरीजों की यह संख्या भी स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती को दर्शाती है।

इस मुद्दे को विधान परिषद में उठाते हुए सदस्य Uma Khapre ने अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और चिकित्सा व्यवस्था की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आईसीयू जैसे संवेदनशील विभाग में पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी बेहद जरूरी होती है, क्योंकि यहां भर्ती मरीजों की स्थिति अक्सर बेहद गंभीर होती है।

मंत्री हसन मुश्रीफ ने जवाब देते हुए कहा कि अस्पताल के आईसीयू में विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद हैं और इलाज की निगरानी अनुभवी चिकित्सकों द्वारा की जाती है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अस्पताल में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक पृष्ठभूमि के इंटर्न भी काम कर रहे हैं। ये इंटर्न अस्पताल के फार्माकोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर की देखरेख में अपनी सेवाएं देते हैं।

सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि इन इंटर्न को इलाज से जुड़े स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। वे केवल वरिष्ठ डॉक्टरों और विशेषज्ञों के निर्देशन में सहायक भूमिका निभाते हैं। फिर भी इस खुलासे के बाद चिकित्सा जगत में यह सवाल उठने लगा है कि क्या आधुनिक चिकित्सा प्रणाली वाले आईसीयू में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के इंटर्न को शामिल करना उचित है।

सरकार ने इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अस्पताल में होने वाली हर मौत की अब विस्तार से जांच की जाएगी। इसके लिए 'डेथ ऑडिट' की व्यवस्था लागू की गई है। इस प्रक्रिया के तहत हर छह महीने में एक विशेष समिति अस्पताल में हुई मौतों की समीक्षा करेगी। समिति यह पता लगाएगी कि मरीजों की मृत्यु बीमारी की गंभीरता के कारण हुई या फिर इलाज के दौरान किसी प्रकार की चूक या प्रणालीगत समस्या इसके लिए जिम्मेदार थी। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से अस्पताल में होने वाली मौतों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित विश्लेषण किया जा सकेगा। इसके आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

राज्यसभा चुनाव में एनडीए का दम, बिहार की सभी सीटें जीतीं, ओडिशा में क्रॉस वोटिंग से भाजपा को बढ़त

देश के कई राज्यों में हुए राज्यसभा चुनावों में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपनी राजनीतिक ताकत का प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। सोमवार को Bihar, Odisha और Haryana की कुल 11 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 14 उम्मीदवार मैदान में थे। शुरुआती नतीजों में बिहार की सभी पांच सीटों और ओडिशा की चार सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं। इनमें से आठ सीटों पर एनडीए समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। इन चुनावों में सबसे अधिक चर्चा क्रॉस वोटिंग की रही, जिसने कई राज्यों में विपक्षी दलों की रणनीति को कमजोर कर दिया। बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों के लिए हुए चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन ने एकतरफा बढ़त हासिल की। मुख्यमंत्री Nitish Kumar के नेतृत्व वाले गठबंधन के उम्मीदवारों ने अपेक्षाकृत आसानी से जीत दर्ज की। इनमें भाजपा के Nitin Naveen, जनता दल (यू) के Ramnath Thakur और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के Upendra Kushwaha शामिल हैं। हालांकि असली मुकाबला पांचवीं सीट के लिए देखने को मिला, जहां भाजपा के Shivesh Kumar और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार A. D. Singh के बीच कड़ा संघर्ष था।

इस सीट पर चुनावी गणित बेहद दिलचस्प हो गया जब विपक्षी दलों के कुछ विधायक मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के तीन और राजद के एक विधायक मतदान में हिस्सा नहीं ले सके।

इस स्थिति का लाभ भाजपा उम्मीदवार को मिला और द्वितीय वरीयता के वोटों की गणना के बाद शिवेश कुमार ने जीत दर्ज कर ली। इस परिणाम ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि विपक्षी दल अपने ही विधायकों को एकजुट रखने में असफल दिखाई दिए।

उधर Odisha में भी चुनावी नतीजों ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। यहां चार सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से दो सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने कब्जा कर लिया। एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई, जबकि एक सीट बीजद को मिली। ओडिशा की राजनीति में लंबे समय से प्रभाव रखने वाले नेता Naveen Patnaik की पार्टी बीजद के लिए यह परिणाम चौंकाने वाला माना जा रहा है।

सबसे बड़ा उलटफेर चौथी सीट पर देखने को मिला, जहां भाजपा समर्थित उम्मीदवार Dilip Ray ने बीजद और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार Dateshwar Hota को हराकर सभी को चौंका दिया। इस सीट पर विपक्षी एकता की रणनीति उस समय ध्वस्त हो गई जब कांग्रेस और बीजद के कुछ विधायकों ने अपनी ही पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग कर दी। इस घटना ने साफ कर दिया कि विपक्षी दलों के भीतर एकजुटता की कमी अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।

हरियाणा में दो सीटों के लिए मतदान हुआ, लेकिन यहां का मामला देर रात तक कानूनी दांव-पेच में उलझा रहा। चुनाव के दौरान भाजपा ने कांग्रेस के दो विधायकों के वोटों पर आपत्ति जताई। इसके जवाब में कांग्रेस ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री Anil Vij के वोट को चुनौती दे दी। इस विवाद के चलते चुनाव प्रक्रिया में तनाव बढ़ गया और देर रात तक चुनाव आयोग के सामने शिकायतों और जवाबों का सिलसिला चलता रहा।

चुनाव अधिकारियों को दोनों पक्षों की आपत्तियों पर विचार करना पड़ा, जिसके कारण मतगणना की प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोक दी गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि हरियाणा में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीत दर्ज करते हैं, तो यह कांग्रेस के लिए लगातार तीसरी बड़ी राजनीतिक हार मानी जाएगी।

इन चुनावों के नतीजों ने यह भी स्पष्ट संकेत दिया है कि विपक्षी गठबंधन अभी भी अपने विधायकों को पूरी तरह एकजुट रखने में सफल नहीं हो पा रहा है। बिहार में Rashtriya Janata Dal और ओडिशा में Biju Janata Dal जैसे मजबूत क्षेत्रीय दलों के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग किए जाने से यह संदेश गया है कि राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं।

राज्यसभा की इन सीटों के चुनाव का महत्व इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि कुल 37 सीटों में से 26 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे। केवल उन्हीं राज्यों में मतदान हुआ जहां सीटों की संख्या से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे। इस स्थिति ने राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति और विधायकों के समर्थन को लेकर बेहद सतर्क रहने पर मजबूर किया।

भाजपा और एनडीए ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाते हुए न केवल अपनी तय संख्या की सीटें सुरक्षित कीं, बल्कि कुछ जगहों पर अपेक्षा से अधिक सफलता भी हासिल की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन परिणामों से यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में संसद के उच्च सदन में एनडीए की स्थिति और मजबूत हो सकती है। वहीं विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने गठबंधन को मजबूत बनाए रखने और विधायकों के बीच अनुशासन कायम रखने की होगी।

कुल मिलाकर इन राज्यसभा चुनावों ने यह दिखा दिया है कि भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति और आंतरिक एकजुटता कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां एनडीए ने रणनीतिक रूप से बढ़त हासिल की, वहीं विपक्षी दलों को अपने संगठन और समन्वय को और मजबूत करने की जरूरत महसूस हो रही है।

संपादकीय

वांगचुक की रिहाई

लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता Sonam Wangchuk की रिहाई ने भारतीय लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के उपयोग को लेकर एक व्यापक बहस को जन्म दे दिया है। पिछले वर्ष सितंबर से राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद रहे वांगचुक को आखिरकार तब राहत मिली जब केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ लगाए गए National Security Act को हटाने का निर्णय लिया। गृह मंत्रालय का कहना है कि यह फैसला लद्दाख में शांति, स्थिरता और संवाद का माहौल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है, जबकि विपक्षी दल इसे सरकार की मजबूरी बता रहे हैं। उनका तर्क है कि 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होने वाली थी और कानूनी स्थिति कमजोर पड़ने के कारण सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा। यह मामला केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी या रिहाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस बड़े सवाल को सामने लाता है कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना भी कभी-कभी अपराध की श्रेणी में आ जाता है। Sonam Wangchuk लंबे समय से लद्दाख के पर्यावरण संरक्षण और वहां के लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। वे न केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं बल्कि वैज्ञानिक सोच और अभिनव प्रयोगों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्हें एशिया के प्रतिष्ठित Ramon Magsaysay Award से भी सम्मानित किया जा चुका है। लद्दाख जैसे दुर्गम और ठंडे क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा, जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिए कई अभिनव प्रयोग किए हैं। "आइस स्तूप" जैसी परियोजना ने विश्व स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि इसके माध्यम से हिमालयी क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने का एक व्यावहारिक समाधान सामने आया। पिछले कुछ वर्षों में वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के प्रमुख चेहरों में से एक बन गए थे। उनका तर्क था कि लद्दाख का पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत नाजुक है और यदि अनियंत्रित विकास या बड़े औद्योगिक निवेश को बिना पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के अनुमति दी गई तो इससे हिमालयी क्षेत्र को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। इसी कारण वे लगातार यह मांग करते रहे कि स्थानीय समुदायों को अधिक संवैधानिक संरक्षण और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी दी जाए। इस मांग को लेकर उन्होंने कई बार अनशन किया, शांतिपूर्ण पदयात्राएं कीं और दिल्ली पहुंचकर भी अपनी बात रखने का प्रयास किया। हालांकि पिछले वर्ष सितंबर में आंदोलन के दौरान कुछ स्थानों पर तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आईं, जिसके बाद प्रशासन ने कठोर कदम उठाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सरकार का कहना था कि आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका थी और इसी कारण उनके खिलाफ National Security Act लागू किया गया। लेकिन विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने इस निर्णय की तीखी आलोचना की। उनका कहना था कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति की आवाज को इस तरह दबाना उचित नहीं है, खासकर तब जब वह व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अधिकारों की बात कर रहा हो। विवाद का एक बड़ा कारण यह भी था कि वांगचुक को उनके गृह क्षेत्र लद्दाख से लगभग 1400 किलोमीटर दूर राजस्थान के जोधपुर जेल में रखा गया था। कई सामाजिक संगठनों ने इसे अमानवीय बताया और सवाल उठाया कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन से जुड़े व्यक्ति को इतनी दूर स्थानांतरित करने की क्या आवश्यकता थी। इसके साथ ही उनकी सेहत को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की गईं। बताया गया कि उन्हें लगातार पेट दर्द की शिकायत हो रही थी और उनकी पत्नी ने अदालत में आवेदन देकर विशेषज्ञ डॉक्टरों से जांच कराने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने यह भी आग्रह किया था कि अदालत के निर्देश पर हर महीने उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि उनकी स्थिति पर नजर रखी जा सके। इस मामले में न्यायपालिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेहत को देखते हुए उनकी हिरासत पर पुनर्विचार करने की बात कही थी। अदालत ने टिप्पणी की थी कि यदि हिरासत के आदेश में कानूनी त्रुटियां पाई जाती हैं तो उसे रद्द किया जा सकता है। इस टिप्पणी के बाद से ही यह संकेत मिलने लगे थे कि सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। अंततः गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हटाने और उन्हें रिहा करने का निर्णय लिया। वांगचुक की रिहाई के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए हैं।

एक रोशन पंजाब के लिए आगे की राह

> "एक बड़ी रैली करके भाजपा ने पंजाब में चुनावी बिगुल फूंकते हुए अपनी दावेदारी जाहिर कर दी। अब फैसला पंजाब के मतदाता को लेना है। वहीं यदि आम आदमी पार्टी पंजाब में दोबारा जीत हासिल करना चाहती है, तो उसे महज 'दिखावा' करने से कहीं ज़्यादा कर दिखाना होगा। यूं भी यह सरहदी सूबा इसलिए खास है कि दिखावेबाजी में रुचि नहीं।

गत सप्ताह की शुरुआत में, मोदी सरकार की विदेश नीति की असफलताओं की गूंज पंजाब विधानसभा में सुनाई दी। यहां भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। निश्चित रूप से ऐसा पहली बार हुआ। यकीकन, प्रस्ताव पारित करने की बात तो छोड़ें, विदेश नीति पर उपदेश देना विधानसभाओं का काम नहीं। लेकिन इन दिनों राजनीति में इतनी कड़ुवाहट है कि ख्यात आर्किटेक्ट ली कॉर्बूजिए द्वारा डिजाइन की गयी पंजाब विधानसभा की शानदार इमारत भी सड़कछाप शोरगुल से बच नहीं पाई।

पंजाब में शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह ने एक बड़ी रैली की। भाजपा ने इस बेहद महत्त्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य में चुनावी बिगुल फूंकते हुए अपनी दावेदारी का मंसूबा जाहिर कर दिया। एक साल से भी कम समय में यहां नई सरकार बनेगी। ऐसे में भाजपा खुद से -और पंजाब से- सवाल कर रही है कि वह उस काम को क्यों नहीं कर सकती जो अब तक सोच से परे था यानि पंजाब को 'केसरिया' रंग में रंग देना। केसरिया रंग यानी बलिदान का रंग- एक जाना-पहचाना और प्रिय, खासकर सिखों के लिए।

अब तक पार्टी की हालत 6-7 विधायकों तक सीमित रही है। भले ही अमित शाह लेनिन के उस कथन से प्रेरणा लेने की कोशिश करें :'मुझे सत्ता सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर पड़ी मिली, उसे उठा लिया' और यूं क्रांति लाने में कामयाब हुए-लेकिन भाजपा, कम से कम फिलहाल, पा रही है कि 'पांच नदियों की धरती' (अब तीन) के लोग कुछ अलग किस्म के हैं।

निस्संदेह, पंजाब तमाम चुनौतियों से रूबरू है। नशे के भंवर से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। इस बारे मेरी सहयोगी अपर्णा बनर्जी की दोआबा क्षेत्र के मैहतपुर में 19 वर्षीय लड़के की मौत की निराशाजनक रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें, महज पंद्रह दिनों में नशे के कारण जान गंवाने वाला वह तीसरा व्यक्ति था। इसके

अलावा, आयेदिन विदेश स्थित गैंगस्टरों के गुर्गों द्वारा पंजाब में दिनदहाड़े अपने दुश्मनों को मारने की खबरें आती रहती हैं।

सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने सभी वित्तीय सावधानियां ताक पर रख एक ऐसा बजट पेश किया, जिसमें हरेक को कुछ न कुछ देने का वादा किया गया है- इसमें महिलाओं के लिए हर माह 1000 रु. प्रति माह (राज्य की 3 करोड़ जनसंख्या की एक-तिहाई अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रु.) देने की बात कही है। इसे बतौर 'ब्रह्मास्त्र' देखा जा रहा है। मगर इतना धन कहां से आयेगा। पंजाब पर पहले ही 4.17 लाख करोड़ रु. कर्ज है व ब्याज अदायगी में ही 1.16 लाख करोड़ खप जाते हैं, वहीं इस राज्य का जीडीपी दूसरे सबसे निचले स्थान पर है।

बड़ी सफाई से, सिर्फ़ महिलाओं पर केंद्रित यह दांव सीधे प्रधानमंत्री मोदी के तरकश से लिया गया– आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह दांव अच्छी तरह सीख लिया। समस्या यह कि पंजाब की आर्थिक हालत खराब है। गत सप्ताह के आखिर में मोहाली में हुआ 'निवेश शिखर सम्मेलन' शायद देर से आयोजित किया, बेशक इसका मकसद अच्छे वादे हैं। बदकिस्मती से, आप ने देश-विदेश में खुद को नये सिरे से खड़ा करने की काबिलियत रखने वाले पंजाबी उद्यमियों के अनुभव का फायदा नहीं उठाया– याद रहे, नवर्निर्माण करने में कनाडा की 2 करोड़ आबादी पंजाब का 24वां जिला बन सकता है। जबकि,पिछली कांग्रेस सरकार के 'पंजाब इनोवेशन मिशन' में कुछ बेहतरीन विचार शामिल थे। अफ़सोस कि मौजूदा मिशन पिछले वाले की परछाई भर है; क्योंकि भगवंत मान की नौकरशाही नए सिरे से सब कुछ करने में इतनी उलझी रही कि उसे अतीत केअच्छे विचारों पर सोचने का समय नहीं बचा।

और यहां भगवंत मान हैं। कुछ दिन पहले लुधियाना में दिए गए एक भाषण में महिलाओं पर की गई अपनी सतही टिप्पणियों के लिए मुख्यमंत्री की कड़ी आलोचना हुई; भले ही यह कहा जाए कि वे तो अपनी युवावस्था की शरारतों को याद कर रहे थे, लेकिन कम भद्दे शब्द भी प्रयोग किए जा सकते थे (जहां तक कांग्रेसी सुखपाल खैहरा द्वारा 1000 रुपये महिला भत्ते को 'नाचने वाली औरतों' से जोड़ने की बात है, पार्टी को तुरंत उन्हें कालापानी भेज देना चाहिए, जहां पर वे पश्चाताप करें और माफी मांगें –आगे, उन्हें पंजाब की महिलाओं के कोप से सावधान रहना होगा)।

पंजाब के तमाम मर्दों को, खैहरा सहित, मालूम हो कि ये 'नाचनेवालियां' ईमानदारी से दिनभर काम करती हैं, और किसी की भीख या खैरात पर निर्भर नहीं हैं। जहां तक सवाल है कि कौन किस 'कठपुतली नचाने वाले' के इशारे पर नाच रहा है– तो इसका फ़ैसला अभी होना बाकी है और यह फ़ैसला जनता करेगी; न सिर्फ़ अगले साल पंजाब में, बल्कि इस साल पश्चिम बंगाल, असम और केरल में भी। लेकिन बात फिर से भगवंत मान की। अपने हीमोग्लोबिन जांच के लिए उनके बार-बार अस्पताल जाने से भौंहें तनती हैं- क्योंकि पंजाब का हीमोग्लोबिन स्तर तो काफ़ी समय से ऊंचा ही बना हुआ है। राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का उनका वादा बेमौसम की इस गर्मी में मृगतृष्णा जैसा लगता है – इसमें किसी अन्य द्वारा कहे 'न खाऊंगा न खाने दूंगा' युग की अनुगूंज सुनाई देती है। जहां तक बात दिल्ली के प्रभाव की है – तो पंजाब जीतने योग्य बहुत बडा ईनाम है; इसे कभी भी 'दिल्ली दरबार' के आगे झुकना पसंद नहीं रहा, और यही वजह है कि पूरे राजनीतिक वर्ग में 'वापसी की यात्रा' की इतनी ज़्यादा मांग है।

अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के दिल्ली वाले नेता यह बुनियादी सच अच्छी तरह समझते हैं। पंजाब की सत्ता, दिल्ली में मिली हार का कोई 'सांत्वना पुरस्कार' नहीं, और न ही यह पूरे देश में पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोई धुरी है। इस राज्य के लिए महत्वपूर्ण रहे स्वाभिमान के अहसास को देश के बंटवारे ने गहरा ज़ख्म दिया, आतंकवाद ने नुकसान पहुंचाया, और फिर राजनीतिक एवं आर्थिक ,दोनों ही स्तरों पर, निवेश की निरंतर कमी ने इसे और भी कमज़ोर किया। यदि आम आदमी पार्टी पंजाब में दोबारा जीत हासिल करना चाहती है, तो उसे महज़ 'दिखावा' करने से कहीं ज़्यादा कर दिखाना होगा–और इसमें महिलाओं के लिए हर माह मिलने वाले 1000 रुपये भी शामिल हैं।

जैसा कि देश के दूसरे हिस्सों में भाजपा ने जातिवादी वोट बैंक के तोड़ में महिलाओं का 'वोट बैंक' बनाने में इतना मुफ्त का धन बांटा है कि उतने में पंजाब का कर्ज़ चुकाया जा सकता था– याद रखना चाहिए कि महिलाएं लाभार्थी या कोई खैरात पाने वाली नहीं या फिर एक 'कोख' मात्र नहीं, जिनसे 'वीर पुरुष' पैदा होते हैं- इनमें कुछ शब्द वे हैं जो गत सप्ताह पंजाब विधानसभा में गूंजे, वे न केवल कानों को चुभने वाले थे बल्कि गहरी पितृसत्तात्मक सोच भी दर्शाने वाले भी है।

पंजाब इसलिए खास है क्योंकि उसे सिर्फ़ दिखावे में कोई दिलचस्पी नहीं। जब कुछ ही महीनों में राज्य में चुनाव होने वाले हैं, जॉन एफ़. केनेडी के शब्दों में कुछ फेरबदल कर कहें तो 'मत पूछिए कि पंजाब आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह कि आप पंजाब के लिए क्या कर सकते हैं'। यही वजह है कि अमित शाह की रैली पर निगाहें रहीं।

1990 के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके दाहिने हाथ एवं पूर्व वित्त सचिव रहे मोंटेक सिंह आहलूवालिया – वे दो पंजाबी, जिन्होंने देश के आर्थिक सुधारों की अगुवाई की और राष्ट्र की दिशा बदल दी– उन्होंने मुझे भाई गुरदास रचित 'वार' का यह श्लोक भेजा था, जिसकी श्लाघा स्वयं गुरु अर्जन देव भी करते थे:'सतगुर नानक प्रगटेया...मिटी धुंध जग चानन होएया' अर्थात गुरु नानक प्रकट हुए, अज्ञान की धुंध छंटी और दुनिया ज्ञान के प्रकाश से नहा उठी!

यदि पंजाब को फिर से रोशनी में नहाना है, तो आगे की राह स्पष्ट है।

प्रेरणा

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से कलियुग तक : भारतीय कालगणना और सांस्कृतिक स्मृति का आधार

भारतीय सभ्यता की एक अनूठी विशेषता यह रही है कि यहां समय की गणना केवल दिनों, महीनों और वर्षों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे ब्रह्मांडीय और दार्शनिक दृष्टि से भी समझने का प्रयास किया गया। हमारे प्राचीन ऋषियों ने समय को युगों, मन्वन्तरों और कल्पों में विभाजित कर एक ऐसी कालगणना प्रणाली विकसित की जो विश्व की सबसे प्राचीन और व्यापक मानी जाती है। इसी परंपरा के अनुसार द्वापर युग का अंत और कलियुग का आरंभ एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना के रूप में देखा जाता है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार लगभग 5127 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन वह क्षण आया जब भगवान Krishna ने पृथ्वी से अपना महाप्रस्थान किया और उसी समय से कलियुग का आरंभ माना गया। भारतीय पंचांग और सांस्कृतिक परंपराओं में यह दिन एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है।

पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि उस समय समुद्र तट पर बसी एक समृद्ध और भव्य नगरी अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रही थी। यह नगरी द्वारका थी, जिसे श्रीकृष्ण की राजधानी के रूप में जाना जाता है। समुद्र की उठती हुई लहरें धीरे-धीरे इस नगर को अपने भीतर समेट रही थीं। यह दृश्य केवल एक नगर के अंत का संकेत नहीं था, बल्कि एक युग के समाप्त होने और नए युग के प्रारंभ का प्रतीक भी था। इतिहास मानो अपने पुराने अध्याय को बंद कर एक नया पृष्ठ खोल रहा था। उस समय भारतीय कालगणना के अनुसार सृष्टि की रचना को 1,96,08,48,000 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और सातवें मन्वन्तर की 28वीं चतुर्युगी का द्वापर युग समाप्त हो रहा था। इसी संधिकाल में कलियुग का आरंभ हुआ, जो आज तक जारी है।

भारतीय धर्मग्रंथों में सृष्टि की आयु और समय की संरचना का अत्यंत विस्तृत वर्णन मिलता है। प्राचीन ग्रंथ Manusmriti के अनुसार सृष्टि की कुल आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मानी जाती है, जिसे एक ब्रह्म दिवस कहा जाता है। इस एक ब्रह्म दिवस में एक हजार चतुर्युगी होती हैं और प्रत्येक चतुर्युगी में चार युग होते हैं—सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। इस प्रकार सृष्टि के आरंभ से अंत तक ये चारों युग हजार-हजार बार आते हैं। इन चतुर्युगियों को 14 मन्वन्तरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक मन्वन्तर के बीच संधिकाल की व्यवस्था भी बताई गई है। सृष्टि की रचना और प्रलय की अवधि समान मानी जाती है और इन दोनों के योग को अहोरात्र कहा जाता है। तीस अहोरात्र मिलकर एक अहोमास बनाते हैं और बारह अहोमास मिलकर एक अहोवर्ष बनता है। इस प्रकार भारतीय कालगणना की यह विशाल संरचना दर्शाती है कि प्राचीन भारत में समय को लेकर कितनी गहरी और वैज्ञानिक दृष्टि विकसित की गई थी।

द्वापर युग के अंत के साथ जुड़ी घटनाओं का उल्लेख महाभारत और अन्य पुराणों में मिलता है। महाभारत युद्ध के बाद यादव वंश के भीतर अनेक घटनाएं घटित हुईं, जिनके परिणामस्वरूप उनका पतन होने लगा। भगवान श्रीकृष्ण के पुत्र और पौत्र भी इस संसार से विदा हो चुके थे। उनके बड़े भाई Balarama ने भी सांसारिक जीवन का त्याग कर वन की ओर प्रस्थान किया। जब श्रीकृष्ण वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बलराम योगमुद्रा में बैठे हुए अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं। इसके बाद श्रीकृष्ण कुछ समय तक वन में विचरण करते रहे। उन्हें ज्ञात था कि उनका अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है और अब उनके पृथ्वी से विदा होने का समय आ गया है।

कथाओं के अनुसार एक दिन वे वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग मुद्रा में विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक बहेलिया जंगल में शिकार की तलाश में था। दूर से उसे श्रीकृष्ण के पैर का तलवा किसी हिरण के मुख जैसा दिखाई दिया और उसने उस पर बाण चला दिया। वह बाण आकर श्रीकृष्ण के पैर में लग गया। जब बहेलिया पास आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भय से कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। श्रीकृष्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि यह सब नियति का विधान है और इसमें उसका कोई दोष नहीं है। इसके बाद उन्होंने योगबल से अपनी इंद्रियों और प्राणों को नियंत्रित किया और शांत भाव से ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गए। परंपराओं के अनुसार यह घटना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन दोपहर लगभग 2 बजकर 27 मिनट 31 सेकंड पर घटी और उसी क्षण से द्वापर युग समाप्त होकर कलियुग का आरंभ माना गया।

भारतीय परंपरा में युग परिवर्तन के साथ ही संवत्सर और ऋतु चक्र का भी नया क्रम आरंभ होता है। इसी कारण हमारे ऋषियों ने पर्व-त्योहारों को प्रकृति के साथ जोड़कर व्यवस्थित किया। चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले नवरात्र इसी व्यवस्था का महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इन दिनों मौसम संतुलित होता है और प्रकृति परिवर्तन के दौर से गुजर रही होती है। इसी कारण इन नौ दिनों में साधना, उपासना और यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठानों की परंपरा विकसित हुई। इन अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। नवरात्र के दौरान दुर्गा अर्थात प्रकृति माता के नौ रूपों की आराधना की जाती है और इसे आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण का समय माना जाता है।

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन भारतीय नववर्ष के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दक्षिण भारत में इसे 'उगादी' या 'युगादी' कहा जाता है, जिसका अर्थ है युग का आरंभ। भारतीय पंचांग की गणना भी इसी दिन से प्रारंभ होती है। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि महाभारत के पश्चात सम्राट Yudhishthira ने इसी दिन हस्तिनापुर के सिंहासन को ग्रहण किया था। बाद के समय में महान समाज सुधारक Dayananda Saraswati ने भी इसी तिथि को Arya Samaj की स्थापना की, जिसने भारतीय समाज में वैदिक परंपराओं के पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण कार्य किया।

इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना लगभग 2083 वर्ष पूर्व घटित हुई जब महान सम्राट Vikramaditya ने विदेशी शकों पर विजय प्राप्त कर भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति को पुनर्स्थापित किया। उनकी इस विजय की स्मृति में जिस संवत की शुरुआत हुई वह विक्रमी संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह संवत ईसा से 57 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था और आज भी भारत के अनेक क्षेत्रों में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारतीय पंचांग और अनेक पर्व-त्योहारों की तिथियां भी इसी आधार पर निर्धारित की जाती हैं। आधुनिक युग में जब वैश्वीकरण और पश्चिमी प्रभाव के कारण भारतीय समाज अपनी अनेक परंपराओं से दूर होता जा रहा है, तब अपनी प्राचीन कालगणना और सांस्कृतिक विरासत को समझना और उसे स्मरण करना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

कौन जीतेगा चुनावी महाभारत? क्या बंगाल में होगा बदलाव? क्या केरल में आखिरी किला बचा पाएंगे वामपंथी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच एक और बड़े मुकाबले की तैयारी शुरू हो चुकी है, जबकि वामपंथ अपने आखिरी किले को बचाने की जंग लड़ने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव केवल राज्यों की सत्ता का सवाल नहीं हैं, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाले निर्णायक राजनीतिक संघर्ष के रूप में उभर रहे हैं। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने विस्तार की रणनीति के साथ मैदान में है, जबकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे भाजपा के बढ़ते प्रभाव को रोकने की आखिरी बड़ी परीक्षा के रूप में देख रहे हैं।देखा जाये तो लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हुए कई विधानसभा चुनावों ने यह संकेत दिया कि भाजपा अभी भी राष्ट्रीय राजनीति की सबसे मजबूत ताकत बनी हुई है। विपक्ष को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन के बाद उसका मनोबल बढ़ेगा, लेकिन बाद के चुनावों में भाजपा ने अपनी पकड़ बनाए रखी। अब पांच राज्यों में हो चुका चुनावी शंखनाद का दौर यह तय करेगा कि क्या भाजपा उन राज्यों में भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकती है जहां अब तक उसे सत्ता नहीं मिली है।

देखा जाये तो इन चुनावों की घोषणा ऐसे समय हुई है जब विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत रूप से तथा एनडीए सरकार पर कई मुद्दों को लेकर लगातार हमला कर रहा है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौता, पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे माहौल में इन चुनावों को जनता के वास्तविक राजनीतिक मूड की परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है।

भाजपा इस चुनावी दौर में असम में सबसे अधिक आत्मविश्वास के साथ उतर रही है। 2016 से राज्य की सत्ता में मौजूद भाजपा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में खुद को मजबूत स्थिति में मान रही है। पार्टी ने बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ और स्थानीय पहचान के मुद्दों को चुनावी बहस के केंद्र में ला दिया है, जिससे चुनावी वातावरण और अधिक तीखा हो गया है।

दूसरी ओर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा अब तक सत्ता से दूर रही है, लेकिन इस बार वह पूरी ताकत के साथ अपनी राजनीतिक उपस्थिति को विस्तार देने की कोशिश कर रही है। इन राज्यों में भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्रीय दल हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भाजपा के सबसे मुखर विरोधियों में शामिल हैं और दोनों ही नेता इस चुनावी मुकाबले में सीधे भाजपा के निशाने पर हैं।

हम आपको बता दें कि चारों राज्यों में भाजपा केवल असम में सत्ता में है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में वह सत्तारुढ़ गठबंधन का हिस्सा है। असम के बाद पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पश्चिम बंगाल में दिखाई देती है, जहां वह तृणमूल कांग्रेस को सीधी चुनौती दे रही है। वहीं तमिलनाडु में भाजपा ने अन्नाद्रमुक के नेतृत्व में एक व्यापक गठबंधन तैयार कर द्रमुक के नेतृत्व वाले मोर्चे को घेरने की रणनीति बनाई है।

केरल का चुनाव अलग मायने रखता है क्योंकि यहां परंपरागत रूप से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ही मुख्य मुकाबले में रहे हैं। लेकिन पिछले चुनावों में भाजपा को करीब 17 प्रतिशत मत मिलने के बाद उसे यहां एक प्रभावशाली कारक के रूप में देखा जाने लगा है। ऐसे में यह चुनाव वामपंथ के लिए अपने आखिरी मजबूत किले को बचाने की चुनौती भी बन गया है।

हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी अभियान की कमान संभालते हुए इन सभी राज्यों में लगातार दौरे और रैलियां की हैं। विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ राजनीतिक संदेश देने की रणनीति अपनाते हुए उन्होंने खास तौर पर पश्चिम बंगाल में अपने हमलों को और अधिक तीखा किया। कोलकाता में आयोजित रैली में उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उनकी राजनीति राज्य में तुष्टिकरण की नीति को बढ़ावा देती है।

भाजपा का दावा है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और धार्मिक पहचान से जुड़े मुद्दों ने व्यापक राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। पार्टी का मानना है कि इन मुद्दों ने राज्य में राजनीतिक ध्रुवीकरण को मजबूत किया है और इससे उसे चुनाव में फायदा मिल सकता है।

ममता बनर्जी 2011 से लगातार सत्ता में हैं और उन्होंने कई बार भाजपा की चुनौती को रोकने में सफलता हासिल की है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 18 सीटें जीतकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया था। इसके बाद हुए चुनावों में भाजपा का मत प्रतिशत लगभग 38 से 39 प्रतिशत के बीच स्थिर रहा है, जिससे पार्टी को उम्मीद है कि इस बार वह ममता बनर्जी के किले में बड़ी सेंध लगा सकती है।

कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं हैं। 2014 के बाद से राष्ट्रीय राजनीति में लगातार कमजोर होती जा रही कांग्रेस अब इन चुनावों के जरिये अपने राजनीतिक अस्तित्व को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि केरल में जीत उसके लिए नई राजनीतिक ऊर्जा लेकर आ सकती है।

असम में कांग्रेस ने गौरव गोगोई जैसे अपेक्षाकृत युवा चेहरे को आगे कर नई रणनीति अपनाई है। पार्टी का लक्ष्य कम से कम इतना प्रदर्शन करना है कि यह धारणा टूट सके कि असम पूरी तरह भाजपा का गढ़ बन चुका है। तमिलनाडु में कांग्रेस द्रमुक के साथ गठबंधन में है, हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर शुरुआती मतभेद भी सामने आए। वहीं अभिनेता विजय की नई पार्टी के उभार ने चुनावी समीकरण को और जटिल बना दिया है, जिससे तीन कोणीय मुकाबले की संभावना बन रही है।

अभियान

चैत्र नवरात्रि : शक्ति उपासना, नवसृजन और आत्मशुद्धि का पावन उत्सव

भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में चैत्र नवरात्रि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण, आत्मशुद्धि और जीवन में नई ऊर्जा के संचार का अवसर भी है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तक चलने वाला यह नौ दिवसीय उत्सव भारतीय नववर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। इस कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह समय प्रकृति, समाज और व्यक्ति के जीवन में नए संकल्पों और नई शुरुआत का संदेश लेकर आता है। इस पर्व में जगतजननी शक्ति की उपासना की जाती है और भक्त पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से देवी की आराधना करते हैं। सनातन परंपरा में माना जाता है कि इन नौ दिनों में देवी शक्तियां विशेष रूप से सक्रिय रहती हैं और भक्तों की साधना का शीघ्र फल प्रदान करती हैं। इसलिए देश के मंदिरों, घरों और तीर्थस्थलों में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिकता का अद्भुत वातावरण दिखाई देता है।

चैत्र नवरात्रि का मूल आधार शक्ति की उपासना है। हिंदू धर्म में शक्ति को सृष्टि की मूल ऊर्जा माना गया है और उसी शक्ति का साकार रूप हैं Durga। देवी दुर्गा केवल एक देवी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा का प्रतीक हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर नामक अत्याचारी असुर ने देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों में अत्याचार फैलाने लगा, तब देवताओं की संयुक्त शक्तियों से देवी दुर्गा का प्राकट्य हुआ। यह दिव्य शक्ति देवताओं की सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक थी। देवी दुर्गा ने नौ दिनों तक महिषासुर के साथ भीषण युद्ध किया और दसवें दिन उसका वध कर संसार को अत्याचार से मुक्त कराया। इसी विजय की स्मृति में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इन नौ दिनों को देवी के नौ रूपों की आराधना का काल माना जाता है।

नवरात्रि के दौरान जिन नौ रूपों की पूजा की जाती है, वे हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायिनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। प्रत्येक रूप का अपना विशेष महत्व और आध्यात्मिक संदेश है। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा से स्थिरता और शक्ति की प्राप्ति मानी जाती है, वहीं ब्रह्मचारिणी तप और साधना का प्रतीक हैं। चंद्रघंटा साहस और वीरता का संदेश देती हैं, कूष्मांडा सृजन और ऊर्जा का प्रतीक हैं। स्कंदमाता मातृत्व और संरक्षण का भाव जगाती हैं, कात्यायिनी न्याय और धर्म की स्थापना का प्रतीक हैं। कालरात्रि भय और अज्ञान के नाश की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, महागौरी शांति और पवित्रता का प्रतीक हैं, जबकि सिद्धिदात्री आध्यात्मिक सिद्धियों और ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। इन नौ दिनों की उपासना मनुष्य के जीवन में शक्ति, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। नवरात्रि का पर्व केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह साधना और आत्मसंयम का भी समय होता है। इन दिनों भक्त उपवास रखते हैं, देवी के मंत्रों का जाप करते हैं और ध्यान व भक्ति के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। उपवास का अर्थ केवल भोजन का त्याग करना नहीं है, बल्कि यह इंद्रियों पर नियंत्रण और आत्मानुशासन का अभ्यास भी है। सात्विक भोजन, संयमित जीवनशैली और सकारात्मक विचारों के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का प्रयास करता है। यही कारण है कि नवरात्रि को आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का पर्व कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि का एक और महत्वपूर्ण पक्ष नवसृजन और नवआरंभ से जुड़ा हुआ है। भारतीय परंपरा के अनुसार इसी दिन ब्रह्मांड की सृष्टि का आरंभ हुआ माना जाता है। इसीलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भारतीय नववर्ष का प्रारंभ भी माना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में इस दिन को अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे नवसंवत्सर के रूप में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहा जाता है और दक्षिण भारत में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे उगादी के नाम से जाना जाता है। इन सभी पर्वों का मूल भाव एक ही है—नए समय का स्वागत और जीवन में नई ऊर्जा का संचार। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चक्र की नई शुरुआत का प्रतीक भी है। नवरात्रि का संबंध स्वास्थ्य और प्रकृति के संतुलन से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत की प्राचीन जीवनशैली में ऋषियों ने पर्व-त्योहारों को प्रकृति के चक्र के अनुसार निर्धारित किया था। चैत्र नवरात्रि का समय सर्दी से गर्मी की ओर संक्रमण का होता है। इस समय शरीर को नई जलवायु के अनुकूल ढालने की आवश्यकता होती है। उपवास, हल्का भोजन और संयमित जीवनशैली शरीर को इस परिवर्तन के लिए तैयार करती है। इस दृष्टि से नवरात्रि का उपवास केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी माना जाता है। मन और शरीर दोनों की शुद्धि इस पर्व का प्रमुख उद्देश्य है।

नवरात्रि के दिनों में पूरे देश में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिलता है। विशेष रूप से शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। उत्तर प्रदेश का विंध्याचल धाम, हिमाचल प्रदेश के Naina Devi Temple और Jwala Ji Temple, असम का Kamakhya Temple और जम्मू-कश्मीर का Vaishno Devi Temple जैसे प्रमुख शक्तिपीठों में लाखों श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इन मंदिरों में अखंड ज्योति, दुर्गा सप्तशती का पाठ, भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान पूरे वातावरण में भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संचार होता है।

चैत्र नवरात्रि का समापन रामनवमी के दिन होता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम Rama के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। रामनवमी के साथ नवरात्रि का समापन इस संदेश के साथ होता है कि जीवन में शक्ति और धर्म दोनों का संतुलन आवश्यक है। देवी दुर्गा की शक्ति और भगवान राम की मर्यादा मिलकर मानव जीवन को आदर्श दिशा प्रदान करती हैं।

नवरात्रि का पर्व समाज को यह भी संदेश देता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की विजय ही होती है। महिषासुर के वध की कथा इसी सत्य का प्रतीक है। यह कथा केवल पौराणिक घटना नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश भी है कि जब समाज में अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, तब सामूहिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से उसका अंत संभव है।

आज के समय में जब जीवन की गति तेज हो गई है और मानसिक तनाव तथा नकारात्मकता बढ़ती जा रही है, तब नवरात्रि जैसे पर्व हमें आत्ममंथन और आत्मसंयम का अवसर प्रदान करते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि वास्तविक शक्ति हमारे भीतर ही निहित है और आस्था, साधना तथा सकारात्मक विचारों के माध्यम से उसे जागृत किया जा सकता है। नवरात्रि की नौ रातें वास्तव में आत्मचिंतन और आत्मविकास की यात्रा का प्रतीक हैं।

अंततः कहा जा सकता है कि चैत्र नवरात्रि केवल देवी पूजा का पर्व नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन, संयम और आस्था का महत्व कितना बड़ा है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और उसे सकारात्मक दिशा में उपयोग करता है, तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। इसी कारण नवरात्रि को शक्ति उपासना और आत्मशुद्धि का महापर्व कहा जाता है, जो हर वर्ष हमें नई ऊर्जा, नई आशा और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

नर्मदा परिक्रमा की जोरशोर से तैयारियाँ : राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए के खर्च से श्रद्धालुओं को प्रदान करेगी अनेक सुविधाएँ

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का 'आस्था के साथ सुरक्षा' का संवेदनशील दृष्टिकोण
- आगामी 19 मार्च से शुरू होगी पवित्र उत्तरवाहिनी पंचकोशी नर्मदा परिक्रमा
- श्रद्धालुओं की परिक्रमा को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार की सेवा-सुविधा की झड़ी
- बिजली, पानी, भोजन, भीड़ नियंत्रण सहित हर प्रकार से साथ रहेगी सरकार
- यात्राधाम विकास बोर्ड ने उठाई परिक्रमा की तमाम जिम्मेदारियाँ

(जीएनएस)। गांधीनगर : भारतीय संस्कृति में सदियों से साधु-संतों तथा श्रद्धालुओं के लिए नर्मदा परिक्रमा केवल यात्रा नहीं; बल्कि आस्था, साधना एवं आध्यात्मिक शक्ति का अनूठा अनुभव रही है और गुजरात में आयोजित होने वाली उत्तरवाहिनी पंचकोशी नर्मदा परिक्रमा इसी सनातन परंपरा का जीवंत प्रतिबिंब है, जहाँ भक्त नर्मदा माता की आराधना के साथ परिक्रमा कर आध्यात्मिक साहस के माध्यम से शांति का अनुभव प्राप्त करते हैं।

गुजरात सरकार भी हर वर्ष आयोजित होने वाली उत्तरवाहिनी पंचकोशी नर्मदा परिक्रमा को भव्य एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएँ करती है। इस वर्ष (गुजराती विक्रम संवत के अनुसार) आगामी फाल्गुन वद अमावस्या 19 मार्च से चैत्र वद अमावस्या 17 अप्रैल, 2026 तक चलने वाली इस 30 दिवसीय नर्मदा परिक्रमा के लिए भी राज्य सरकार ने जोरशोर से तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए 'विकास भी, विरासत भी' मंत्र का अनुकरण करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा गुजरात में भी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के साथ आधुनिक सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के संवेदनशील नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में राज्य सरकार नर्मदा परिक्रमा के लिए ऐसी व्यवस्थाएँ कर रही है कि जिसमें श्रद्धा, सुरक्षा एवं सुविधा; तीनों का संगम देखने को मिलेगा।

स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता

यात्राधाम बोर्ड द्वारा परिक्रमा क्षेत्र को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद रखने की विशेष व्यवस्था की गई है। महिला-पुरुष के लिए अलग अस्थायी शौचालय, मोबाइल टॉयलेट वैन तथा स्नान सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी। निर्बाध जलापूर्ति, ड्रैनज तथा कूड़ा निकासी की सुनियोजित व्यवस्थाएँ की गई हैं। एक महीने की परिक्रमा के दौरान हाउसकीपिंग टीमें अनेक शिफ्टों में कार्यरत रहेंगी, जिससे परिक्रमा क्षेत्र स्वच्छ व सुव्यवस्थित रहे।

सुरक्षा तथा आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ क्राउड मैनेजमेंट

लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाई गई है। पुलिस बूथ, सुरक्षा केबिन तथा वॉच टावर खड़े किए जा रहे हैं। प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारी अनेक शिफ्टों में सतत ड्यूटी पर रहेंगे। भीड़ नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार की बैरिकेडिंग व्यवस्था तथा इन्फ्रारेड (आईआर) एवं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) आधारित हेड काउंट सिस्टम द्वारा श्रद्धालुओं के आवागमन पर आधुनिक टेक्नोलॉजी द्वारा नजर रखी जाएगी।

अब स्थायी सुविधाओं पर बल : 5.07 करोड़ रुपए की लागत से परमानेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार

राज्य सरकार के सहयोग से यात्राधाम बोर्ड अब नर्मदा परिक्रमार्थियों के लिए धीरे-धीरे स्थायी सुविधाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रहा है। अब तक 5.07 करोड़ रुपए की लागत से स्थायी सुविधाओं के विकास कार्य पूरे किए गए हैं, जो परिक्रमार्थियों के लिए स्थायी राहत का आधार बनेंगे। इनमें (1) श्री मढ़ी देवस्थान में लगभग 99.68 लाख रुपए की लागत से पेवर ब्लॉक पाथवे, सुविधा केन्द्र, पीने के पानी की बड़ी टंकी, सोलर लाइट तथा शौचालय ब्लॉक (2) श्री सिद्धटेकरी राम कुंड में 226.93 लाख रुपए के कार्यों के अंतर्गत रिटेनिंग वॉल, परिक्रमार्थी सुविधा केन्द्र, शौचालय, पेयजल, यात्री निवास का नवीनीकरण, शेड, इलेक्ट्रिफिकेशन, बोरवेल, सोलर लाइट तथा ड्रैनेज सिस्टम का निर्माण और (3) श्री बलबला कुंड में अनुमानित 149.87 लाख रुपए की लागत से परिक्रमार्थी सुविधा केन्द्र, शौचालय, पेयजल, इलेक्ट्रिफिकेशन तथा पाथवे जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। इस प्रकार; गुजरात सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के दिशानिर्देश में राज्य की सांस्कृतिक-सनातन परंपराओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दे रही है।

लाइटिंग, कम्युनिकेशन तथा सर्वेलांस की आधुनिक सुविधाएँ

परिक्रमा मार्ग तथा सभी घाटों को प्रकाशित करने के लिए व्यापक लाइटिंग व्यवस्था की जा रही है। समग्र परिक्रमा मार्ग पर एलईडी व फ्लड लाइट लगाई जाएंगी, जिससे रात के समय यात्रियों को सुरक्षि व स्पष्ट मार्ग मिले। सार्वजनिक उद्घोषणाओं के लिए साउंड सिस्टम, वायरलेस कम्युनिकेशन तथा सीसीटीवी सर्वेलांस की व्यवस्था रहेगी। टेक्निकल ऑपरेटर समग्र क्षेत्र में निरंतर नजर रखेंगे।

5.41 करोड़ रुपए की लागत से अस्थायी सुविधाओं का व्यापक विस्तार

नर्मदा परिक्रमार्थियों की 'दुर्गम' यात्रा को 'सुगम' बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड (जीपीवाईवीबी) द्वारा परिक्रमा के दौरान उमड़ने वाले हजारों श्रद्धालुओं को आरामदायक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए के खर्च से बड़े पैमाने पर स्थायी व अस्थायी ढाँचागत सुविधाएँ स्थापित की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष यानी 2025-26 में परिक्रमा के लिए लगभग 5.41 करोड़ रुपए की लागत से अस्थायी सुविधाएँ मजबूत बनाई जा रही हैं। इनमें अतिरिक्त डोम शेल्टर, मोबाइल टॉयलेट, वॉटर स्टेशन, मेडिकल यूनिट, 24 X 7 एम्बुलेंस, लाइटिंग तथा इमर्जेंसी हेल्प पॉइंट, विशाल वॉटरप्रफू डोम शेल्टर में यात्रियों के लिए चारपाई, गद्दे, तकिये, कुर्सी तथा बेडशीट से युक्त बैठक व विश्राम की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ; स्नानगृह, चेंजिंग रूम व क्लोक रूम की व्यवस्था की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए सेवा केन्द्रों व दुकानों की व्यवस्था की जा रही है।

'अंत्योदय' तथा 'गरीब कल्याण' के मंत्र के साथ सुदूरवर्ती व्यक्ति की अन्न सुरक्षा के लिए सरकार संकल्पबद्ध : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी

- राज्य के अनाज वितरण में आधुनिक टेक्नोलॉजी का नया युग : सीबीडीसी डिजिटल फूड कूपन और 'अन्नपूर्ति' ग्रेन एटीएम कार्यरत
- राज्य के किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय : 'श्री अन्न-मिलेट्स' की खरीद पर प्रति क्विंटल 300 रुपए का बोनस प्रावधान

(जीएनएस)। गांधीनगर : गांधीनगर में आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी ने विभाग की नई व्यवस्थाओं के बारे में कहा कि 'अंत्योदय' तथा 'गरीब कल्याण' के मंत्र के साथ राज्य में सुदूरवर्ती व्यक्ति की खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। गुजरात के वर्ष 2026-27 के बजट में इस विभाग के लिए कुल 2,856 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है, जो राज्य सरकार की गरीबों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। 'गरीब कल्याण' मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का केवल एजेंडा नहीं, बल्कि मंत्र है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय' के सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार लगातार कार्यरत है।

इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा ग्राहक सुरक्षा राज्य मंत्री श्री पी.सी. बरंडा विशेष रूप से उपस्थित रहे।

पत्रकार सम्मेलन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती मोना खंधार ने प्रस्तुति देते हुए कहा कि राज्य के नागरिकों को अन्न सुरक्षा तथा पोषणयुक्त आहार मिले, इसके लिए वर्ष 2026-27 के बजट में राज्य के लगभग 75 लाख एनएफएसए परिवारों को अन्न सुरक्षा प्रदान करने के लिए 700.63 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए संतुलित आहार के लिए एनएफएसए कार्डधारकों को राहत दर पर अरहर दाल और चना उपलब्ध कराने के लिए 841.69 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2025-26 में पिछले वर्ष की तुलना में दालों के वितरण में 28,491 मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त आयोडीन तथा आयरन की कमी दूर करने के लिए 75 लाख परिवारों को केवल 1 प्रति किलोग्राम की दर से डबल फोर्टिफाइड नमक उपलब्ध कराने के लिए 59.49 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से पारदर्शिता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार समाप्त करने और सब्सिडी का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का विस्तार किया गया है। गुजरात ने देश में पहली बार सीबीसीडी (सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी) आधारित डिजिटल फूड कूपन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह प्रणाली ई-केवायसी आधारित होने के कारण बायोमेट्रिक विफलता जैसी समस्याओं का समाधान करेगी। अपर मुख्य सचिव ने जोड़ा कि अब तक राज्य के 4.23 करोड़ राशन कार्ड सदस्यों का ई-केवायसी पूरा किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त किसान कल्याण के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को उचित मूल्य मिले; इसके लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की जा रही है। वर्ष 2025-26 में 40,396 किसानों से विभिन्न अनाजों की खरीद कर 47,494 लाख रुपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया है। श्री अन्न (मिलेट्स) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बाजरा, ज्वार, रागी और मक्का की खरीद पर किसानों को 300 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन बोनस देने के लिए 36.51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

श्रीमती मोना खंधार ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की महत्वपूर्ण कड़ी 17 हजार से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों के कमीशन में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 150 के बजाय 185 प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाएगा। इसके लिए 67.20 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। 'सजग ग्राहक, सुरक्षित गुजरात' के मंत्र के साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नई पहल की गई है। राज्य के प्रत्येक जिले में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में 'प्री-लिटिगेशन और समाधान केंद्र' स्थापित किए जाएंगे, जिससे शिकायतों का अदालत की लंबी प्रक्रिया के बिना तेजी से समाधान हो सकेगा। उन्होंने जोड़ा कि इसके अतिरिक्त कानूनी माप विज्ञान तंत्र की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इन्वेस्टर फेसीलिटेशन पोर्टल (आईएफपी) भी शुरू किया गया है।

इस पत्रकार सम्मेलन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निदेशक श्री मयूर मेहता सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा ग्राहक सुरक्षा विभाग की अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं :

अन्नपूर्ति (ग्रेन एटीएम) :

24×7 अनाज उपलब्ध कराने के लिए 'मेड इन गुजरात' ग्रेन एटीएम सुविधा शुरू की जाएगी। इसमें लाभार्थी मात्र 35 सेकंड में 25 किलोग्राम अनाज प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है

संभावित रूप से कलोल में अन्नपूर्ति (Grain एटीएम) का शुभारंभ किया जाएगा

नए आईटी सेल का गठन :

स्मार्ट-पीडीएस प्रणाली के मजबूत क्रियान्वयन के लिए विभाग में नया आईटी सेल बनाने के लिए 2.49 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है

लैबोरेटरी उपकरणों की खरीद :

कानूनी माप विज्ञान तंत्र के लिए 67 वर्किंग स्टैंडर्ड लैबोरेटरी उपकरणों की खरीद के लिए 28.38 करोड़ रुपए का प्रावधान

नए गोदामों का निर्माण :

राज्य में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए नाबार्ड की सहायता से 45 तहसीलों में 51 नए गोदाम बनाने की योजना, जिससे 93,400 मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित होगी

पैकेज्ड वितरण व्यवस्था :

अरहर दाल, चना और चीनी के वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने और शिकायतें कम करने के लिए अब खुले के बजाय 1 किलोग्राम के प्रमाणित पैक में वितरण किया जाएगा

कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडेक्स (सीआरआई) :

विश्व में पहली बार कंपनियों को उपभोक्ताओं के प्रति व्यवहार और शिकायत निवारण के आधार पर रेटिंग देने के लिए सीआरआई तैयार करने के लिए एमओयू किए गए हैं

वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और लॉजिस्टिक्स में रुकावटों का व्यापार के माहौल पर असर; निर्यात फिर भी मज़बूत: फियो अध्यक्ष, श्री एस सी रल्हन

(जीएनएस)। नई दिल्ली; 16 मार्च, 2026: फरवरी 2026 के ताज़ा व्यापार डेटा पर टिप्पणी करते हुए, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइज़ेशन्स (फियो) के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने कहा कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं, सप्लाई चेन में रुकावटों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत का निर्यात क्षेत्र मज़बूती दिखाता रहा है।

सरकारी डेटा के अनुसार, फरवरी 2026 में भारत का वस्तु निर्यात 36.61 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 0.81 प्रतिशत की मामूली गिरावट दिखाता है। वस्तु आयात 24.11 प्रतिशत बढ़कर 63.71 अरब डॉलर हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 27.1 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ, जो जनवरी 2026 की तुलना में कम हुआ है। हालाँकि, कुल निर्यात (वस्तु और सेवाएँ मिलाकर) साल-दर-साल लगभग 11 प्रतिशत बढ़कर 76.13 अरब डॉलर हो गया, जबकि कुल आयात लगभग 22 प्रतिशत बढ़कर 80.09 अरब डॉलर हो गया, जो मज़बूत सेवा निर्यात और लगातार घरेलू माँग को दर्शाता है।

अप्रैल-फरवरी वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, भारत का वस्तु निर्यात 402.93 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें 1.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि आयात 8.53 प्रतिशत बढ़कर 713.53 अरब डॉलर हो गया। इस अवधि के दौरान कुल वस्तु और सेवा निर्यात का अनुमान 790.86 अरब डॉलर लगाया गया है, जबकि पिछले साल यह 747.58 अरब डॉलर था, जो 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

श्री रल्हन ने कहा कि मध्य पूर्व में अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ता संघर्ष वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता को बढ़ा रहा है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य और लाल सागर सहित प्रमुख समुद्री मार्गों में रुकावटों के कारण जहाज़ों को अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है, जिससे माल ढुलाई की लागत, बीमा प्रीमियम और यात्रा का समय बढ़ गया है, जिससे निर्यातकों पर दबाव बढ़ रहा है।

इन चुनौतियों के बावजूद, भारत का निर्यात क्षेत्र मज़बूती दिखाता रहा है। इसे अलग-अलग बाज़ारों और इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाएँ, रत्न और आभूषण, रसायन, तैयार कपड़े, सूती धागा और कपड़ा, चावल और समुद्री उत्पादों जैसे अहम क्षेत्रों में मज़बूत प्रदर्शन का सहारा मिला है। निर्यात के मुख्य गंतव्य अमेरिका, यूएई, चीन, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, जर्मनी, सऊदी अरब, बांग्लादेश, सिंगापुर और हॉन्गकॉन्ग बने रहे।

श्री रल्हन ने ज़ोर देकर कहा कि निर्यात की गति को बनाए रखने के लिए भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर बारीकी से नज़र रखना, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को सुचारू बनाए रखना और समय पर नीतिगत सहायता देना ज़रूरी होगा। उन्होंने आगे कहा कि बाज़ारों का लगातार विस्तार करना, क्षेत्रीय व्यापार साझेदारियों को मज़बूत बनाना और लॉजिस्टिक्स की कार्यक्षमता को बेहतर बनाना भारत को वैश्विक बाधाओं से निपटने और निर्यात में बढ़ोतरी बनाए रखने में मदद करेगा।

ट्रेन संख्या 19201 भावनगर टर्मिनस - अयोध्या कैंट एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन एवं ठहराव अस्थायी रूप से निरस्त

(जीएनएस)। उत्तर रेलवे द्वारा अवसंरचना उन्नयन कार्यों के अंतर्गत कानपुर सेंट्रल – लखनऊ जंक्शन रेलखंड में कानपुर सेंट्रल–कानपुर पुल बायाँ किनारा सेक्शन स्थित ब्रिज संख्या 110 पर स्टील ट्रफ हटाने तथा एच-बीम स्लीपर उपलब्ध कराने हेतु 42 दिनों का मेगा ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कार्य के कारण कुछ ट्रेनों के संचालन में अस्थायी परिवर्तन किया गया है। इसी क्रम में पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल द्वारा संचालित ट्रेन संख्या 19201 भावनगर टर्मिनस – अयोध्या कैंट एक्सप्रेस को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा।

निर्धारित कार्यक्रमानुसार यह ट्रेन अपने नियमित मार्ग कानपुर सेंट्रल – लखनऊ जंक्शन – अयोध्या कैंट के स्थान पर कानपुर सेंट्रल – प्रयागराज जंक्शन – माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जं. – सुल्तानपुर – अयोध्या कैंट मार्ग से संचालित की जाएगी।

यह व्यवस्था निम्न तिथियों पर लागू रहेगी — 06 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, 27 अप्रैल, 04 मई एवं 11 मई, 2026।

मार्ग परिवर्तन के दौरान कुछ स्टेशनों पर इस ट्रेन का ठहराव अस्थायी रूप से निरस्त रहेगा। परिणामस्वरूप उपरोक्त तिथियों में यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन एवं बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकेगी।

यात्रियों की सुविधा हेतु अनुरोध है कि यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व ट्रेन की अद्यतन जानकारी भारतीय रेल की अधिकृत वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in, एनटीईएस (NTES) अथवा रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 के माध्यम से अवश्य प्राप्त कर लें।

भारत के भू-तापीय ऊर्जा भविष्य को गति: PDEU में 8वां अंतरराष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा सम्मेलन आयोजित

(जीएनएस)। 16 मार्च 2026 को Pandit Deendayal Energy University (PDEU), गांधीनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जियोथर्मल एनर्जी (CEGE) द्वारा 8वां अंतरराष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा सम्मेलन आयोजित किया गया। "Building the Ecosystem through Policy & Partnership" थीम पर आधारित इस सम्मेलन का संचालन SPE PDEU Student Chapter द्वारा किया गया। इस अवसर पर देश-विदेश के प्रमुख वैज्ञानिक, नीति-निर्माता, शिक्षाविद और उद्योग विशेषज्ञ एक मंच पर एकत्र हुए और भारत में भू-तापीय ऊर्जा के विकास से जुड़ी संभावनाओं और चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की। सम्मेलन का उद्घाटन S. Sundar Manoharan, डायरेक्टर जनरल, PDEU द्वारा किया गया। उन्होंने भारत में भू-तापीय ऊर्जा के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए अकादमिक संस्थानों, उद्योग और सरकारी एजेंसियों के बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

सम्मेलन में Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और भू-तापीय ऊर्जा के प्रति सरकार की बढ़ती प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इस अवसर पर Sangita M. Kasture, साइंटिस्ट-G, MNRE ने PDEU के भू-तापीय अनुसंधान केंद्र में हो रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शोधकर्ताओं की निरंतर मेहनत और समर्पण ने इस केंद्र को भारत के प्रमुख भू-तापीय अनुसंधान एवं विकास केंद्रों में स्थापित कर दिया है।

अपने संबोधन में डॉ. कस्तुरे ने सितंबर 2025 में जारी MNRE की भू-तापीय नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार विशेष रूप से लो से मीडियम एन्थैल्पी भू-तापीय प्रणालियों के अन्वेषण और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इन प्रणालियों में स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन की बड़ी क्षमता है, जो क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत कर सकती है।

उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी भू-तापीय तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रकार का सहयोग भू-तापीय डेमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स को विकसित करने में सहायक होगा, जो इस तकनीक की व्यावहारिक और आर्थिक उपयोगिता को प्रदर्शित कर सकते हैं।

डॉ. कस्तुरे ने हाइब्रिड भू-तापीय प्रणालियों की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यदि भू-तापीय ऊर्जा को सौर और पवन जैसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के साथ जोड़ा जाए तो इससे ऊर्जा उत्पादन की दक्षता और विश्वसनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

सम्मेलन में Akhouri Bishwapriya, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, Geological Survey of India (GSI) ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने पूर्वी भारत में भू-तापीय ऊर्जा की अपार लेकिन अभी तक काफी हद तक अनछुई संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से मुंगेर–सहरसा रिज के भू-वैज्ञानिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह क्षेत्र भू-तापीय संसाधनों के दृष्टिकोण से अत्यंत संभावनाशील है, लेकिन अभी भी पर्याप्त रूप से अन्वेषित नहीं हुआ है।

सोना वायदा 2263 रुपये और चांदी वायदा 6835 रुपये लुढ़का: क्रूड ऑयल वायदा में 39 रुपये की नरमी

(जीएनएस)। मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 290904.31 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 33765.42 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 257137.85 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मार्च वायदा 38122 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 4937.22 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 22416.91 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 157347 रुपये के भाव पर खूलकर, 157523 रुपये के दिन के उच्च और 154925 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 158466 रुपये के पिछले बंद के सामने 2263 रुपये या 1.43 फीसदी लुढ़ककर 156203 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 2022 रुपये या 1.56 फीसदी घटकर 127825 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 262 रुपये या 1.61 फीसदी घटकर 16029 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी अप्रैल वायदा 158400 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 158400 रुपये और नीचे में 154919 रुपये पर पहुंचकर, 2278 रुपये या 1.44 फीसदी घटकर 156249 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम 159002 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159002 रुपये और नीचे में 155700 रुपये पर पहुंचकर, 159582 रुपये के पिछले बंद के सामने 2599 रुपये या 1.63 फीसदी घटकर 156983 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सत्र के आरंभ में 255101 रुपये के भाव पर खूलकर, 257161 रुपये के दिन के उच्च और 246862 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 259435 रुपये के पिछले बंद के सामने 6835 रुपये या 2.63 फीसदी गिरकर 252600 रुपये प्रति किलो हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 7678 रुपये या 2.89 फीसदी लुढ़ककर 257990 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 7718 रुपये या 2.9 फीसदी गिरकर 258179 रुपये प्रति किलो हुआ।

- कमोडिटी वायदाओं में 33765.42 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 257137.85 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 22416.91 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 38122 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 2812.79 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा 10.9 रुपये या 0.92 फीसदी औंधकर 1176.5 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता मार्च वायदा 1.9 रुपये या 0.59 फीसदी घटकर 322.55 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 4.05 रुपये या 1.17 फीसदी लुढ़ककर 342.05 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि सीसा मार्च वायदा 2.2 रुपये या 1.17 फीसदी घटकर 186.4 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 8445.16 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा 9100 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 9341 रुपये और नीचे में 8936 रुपये पर पहुंचकर, 39 रुपये या 0.43 फीसदी औंधकर 9013 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 31 रुपये या 0.34 फीसदी गिरकर 9016 रुपये प्रति बैरल हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा 289.3 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 291.5 रुपये और नीचे में 284.8 रुपये पर पहुंचकर, 291.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 5 रुपये या 1.71 फीसदी घटकर 286.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 4.8 रुपये या 1.65 फीसदी गिरकर 286.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा 988 रुपये पर खूलकर, 4.5 रुपये या 0.45 फीसदी गिरकर 996 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 13860.66 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 8556.25 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1972.34 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 570.68 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 27.07 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 231.11 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 7073.88 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1332.28 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 6.53 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 1.62 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 11314 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 62201 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 31962 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 458569 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 65092 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 6721 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 19746 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 77347 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 26450 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 27144 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 38440 पॉइंट पर खूलकर, 38444 के उच्च और 38122 के नीचले स्तर को छूकर, 1177 पॉइंट घटकर 38122 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

सूरत में अयोग्य बिल्डरों द्वारा की गई धोखाधड़ी और जनहित की रक्षा के लिए कार्रवाई की आवश्यकता

(जीएनएस)। हम आमतौर पर देखते हैं कि प्रत्येक व्यवसायी के पास अपना व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस होता है। यह लाइसेंस सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी किया जाता है। जैसे डेयरी लाइसेंस खाद्य विभाग द्वारा, दवा लाइसेंस चिकित्सा बोर्ड द्वारा और वाहन लाइसेंस सड़क यातायात प्राधिकरण (आरटीओ) द्वारा जारी किया जाता है। सरकार, कलेक्टर कार्यालय या किसी अन्य सरकारी कार्यालय द्वारा बिल्डरों को ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दिया जाता है। आज शहर में स्थिति यह है कि कुछ छोटे-बड़े निर्माण कार्य कर रहे हैं और निर्माण ठेके लेकर बिल्डर बन गए हैं, जबकि वे जन्मजात बिल्डर नहीं हैं। ऐसे लोग जो बिल्डर की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ऐसे छोटे-बड़े निर्माण कार्य करते समय बिल्डर का कोई लाइसेंस आवंटित नहीं किया जाता है। बल्कि निर्माण के लिए सरकार और स्वायत्त संगठनों से अनुमति लेनी पड़ती है।

जब ऐसे बिल्डर समाज को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, यानी अपने सिर पर छत थोपने की कोशिश करते हैं या आम लोगों में भय पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे बिल्डरों को अहंकारी और दबंग माना जाता है, और उनके लिए इससे अधिक सम्मान नहीं होता है।

इसलिए, जनता बिल्डरों को यह शपथ नहीं देती कि आप उनके चाचा या मामा नहीं हैं। बिल्डर बनने के अलावा, बिल्डर बनना आपको धोखाधड़ी करने का लाइसेंस नहीं देता, कि आप निर्माण के नाम पर किसानों या जनता, व्यापारियों और आम लोगों को धोखा दें, या जनता के पैसे से उन्हें ठगें और आलीशान कारों में घूमें, आलीशान बंगलों या फ्लैटों में रहें और लोगों को लाल पानी पिलाकर धोखा दें।

ऐसे बिल्डर लुभावने विज्ञापनों वाले बड़े-बड़े होर्डिंग लगाते हैं, दलालों के माध्यम से 30%-35% बुकिंग एडवांस लेते हैं, लेकिन साइट पर 2-3 साल तक कोई निर्माण कार्य नहीं होता और 10-12 साल बाद भी परियोजनाएं पूरी नहीं होतीं। न तो कब्जा मिलता है और न ही बुकिंग राशि वापस की जाती है। इस तरह वे जरूरतमंद लोगों से फ्लैट और दुकानों के नाम पर खुलेआम धोखाधड़ी करते हैं। जरूरतमंदों से पैसे लेने के बाद, वे उन्हें बुक की गई दुकान या फ्लैट का कब्जा नहीं देते, बल्कि उन्हें शांति से जवाब तक नहीं देते और खुलेआम धमकाते हैं और कहते हैं कि जो कर सकते हो करो। वे खुलेआम उन्हें डराते हैं। सिर्फ एक रुपये की डायरी पर लिखी बातों के आधार पर वे कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बिल्डर भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह बिल्डर परियोजनाओं पर लिए गए ऋण पर ब्याज चुकाते हैं, उसी तरह 30%-35% बुकिंग करने वालों को भी ब्याज सहित राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। भले ही निर्माणकर्मी खुद को समाज में सम्मानित व्यक्ति मानते हों, फिर भी अपराध तो अपराध ही होते हैं। और उन्हें अपराधी कहना गलत नहीं है।

सूरत शहर में प्राइम शॉपर्स बिल्डर्स द्वारा किए जा रहे धोखाधड़ी के मामले में, दैनिक समाचार पत्र 'न्यूज़ लाइन' (डायरेक्ट न्यूज़ सूरत) के संपादक छगनलाल मेवाड़ा ने जनहित में जांच पड़ताल करते हुए खबर प्रकाशित की थी कि सुमित गोयनका एक बड़ा घोटाला करके फरार हो जाएगा। छह महीने बाद यह खबर सच साबित हुई और सुमित गोयनका के खिलाफ वेसु पुलिस स्टेशन में 800 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करके फरार होने का मामला दर्ज किया गया। सुमित गोयनका को पुलिस ने दिल्ली से पापड़-खाखरा बेचने का दिखावा करते हुए पकड़ा। अब वह सूरत शहर में ही बस गया है। और जिनके पैसे उसमें गए हैं, वे आर्थिक संकट में फंस गए हैं।

सुमित गोयनका, जो सूरत के प्राइम शॉपर्स वेसु रोड स्थित एक किराए के कार्यालय का प्रबंधन करता था और उनके साथ कारोबार करता था, एक प्रतिष्ठित बिल्डर, बड़े किसान, प्रसिद्ध दलाल और बड़े भूमि सौदों के दलालों से जुड़ा हुआ था। वहां प्रतिदिन करोड़ों रुपये के सौदे होते थे, जिनमें ज्यादातर बिल्डर भी शामिल होते थे। बिहार से आए इसी सुमित गोयनका ने 800 करोड़ रुपये का घोटाला किया।

सामाजिक सुधार और आंदोलन के माध्यम से जनहित के लिए लोगों का संगठित कार्य

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। हममें से कई लोग व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से सामाजिक सुधार के लिए काम कर रहे हैं। कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कुछ अंधविश्वासों को दूर करने के लिए, कुछ सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए, कुछ पर्यावरण संरक्षण के लिए, कुछ बाल अधिकारों के लिए, कुछ महिला अधिकारों के लिए, कुछ मानवाधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। इन सभी व्यक्तियों और संस्थानों के बीच उचित समन्वय आवश्यक है। एक व्यापक सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।

विभिन्न पेशेवर संगठन भी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। विभिन्न समाज (आदिवासी समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज, श्रमिक समाज, किसान समाज, देवी-देवता समाज आदि) अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे आंदोलन अहिंसक तरीके से चलाए जाने चाहिए।

गांधीवादी मानवतावाद में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को आंदोलनकारियों का समर्थन करना चाहिए। यहाँ सवाल यह है कि लोगों को आंदोलन क्यों करने पड़ते हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि शासक आम जनता के हितों के प्रति उदासीन हैं। शासक और अधिकांश बड़े प्रशासनिक अधिकारी, बड़े उद्योगपति, धनी लोग आम जनता के हितों को बनाए रखने के लिए शासन और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हें आम जनता की समस्याओं की कोई चिंता नहीं है।

किसी भी शासक से जुड़े व्यक्ति, संगठन या संस्था को, चाहे वे किसी आंदोलन का समर्थन करें या विरोध करें, आंदोलन से दूर रखना आवश्यक है। जनहित में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अधिकतर वे शासकों के इशारे पर आंदोलनकारियों को गुमराह करने का काम करते हैं। यदि वे व्यापक जनहित में आंदोलनकारियों के साथ रहना चाहते हैं, तो उन्हें शासकों से अपना समर्थन या संबंध छोड़ना होगा। यदि शासकों का शासन और उनके कानून अन्यायपूर्ण हैं, तो उन सभी को मिलकर आंदोलन का विरोध करना चाहिए। हमें एक ऐसी शासन प्रणाली बनानी होगी जो सर्वोपरि जनता, यानी अंतिम व्यक्ति के हितों का ध्यान रखे। हमें

स्थापित हितों पर आधारित मौजूदा शासन प्रणाली को भी समझना चाहिए और उसके विकल्पों पर विचार करना चाहिए।

अंततः, हम सभी को मिलकर ऐसी स्थिति बनानी होगी जहाँ लोगों को किसी भी प्रकार का आंदोलन करने की आवश्यकता न पड़े। इस लेख के लेखक भी एक सामाजिक सेवा संगठन से जुड़े हुए हैं, और वे सभी धर्मों में समानता और वसुधैव कुटुंबम की भावना से प्रेरित होकर, जनहित को प्राथमिकता देते हुए और मीडिया के माध्यम से जन समस्याओं को आवाज़ देते हुए समाज की सेवा करके एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं।

जन्म के 11 घंटे बाद रेफर, एसएसजी अस्पताल में जटिल सर्जरी से नवजात को मिला नया जीवन

(जीएनएस)। गुजरात के Vadodara स्थित Sir Sayajirao General Hospital (एसएसजी अस्पताल) के डॉक्टरों ने एक बार फिर अपनी चिकित्सा दक्षता और समर्पण का परिचय देते हुए गंभीर जन्मजात बीमारी से पीड़ित एक नवजात शिशु की सफल सर्जरी कर उसे नई जिंदगी दी है। पंचमहाल जिले के Godhra की रहने वाली 24 वर्षीय कल्पनाबेन ने 2.600 किलोग्राम वजन के बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन जन्म के तुरंत बाद डॉक्टरों को शिशु में एक गंभीर जन्मजात विकार का संदेह हुआ। जांच के बाद पता चला कि बच्चे को Tracheoesophageal Fistula नामक दुर्लभ और गंभीर बीमारी है।

इस बीमारी में नवजात की खाने की नली यानी इसोफेगस और सांस की नली यानी ट्रेकिया आपस में असामान्य रूप से जुड़ी होती हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे द्वारा पिया गया दूध भोजन नली से पेट में जाने के बजाय सांस की नली के रास्ते फेफड़ों में पहुंच सकता है, जिससे संक्रमण, सांस लेने में कठिनाई और यहां तक कि मौत का खतरा भी पैदा हो जाता है। डॉक्टरों के अनुसार यह स्थिति नवजातों के लिए अत्यंत खतरनाक मानी जाती है और समय रहते इलाज न मिले तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए जन्म के केवल 11 घंटे के भीतर ही उसे गोधरा से वडोदरा के एसएसजी अस्पताल के नवजात गहन चिकित्सा कक्ष (NICU) में रेफर कर दिया गया। अस्पताल पहुंचते ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उसकी जांच शुरू की और पूरी स्थिति का आकलन किया। जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि बच्चे की जान बचाने के लिए जल्द से जल्द सर्जरी करना जरूरी है। डॉक्टरों ने अगले ही दिन ऑपरेशन करने का फैसला लिया। यह सर्जरी अत्यंत जटिल मानी जाती है, क्योंकि इसमें नवजात की बेहद नाजुक स्थिति के बीच खाने की नली और सांस की नली के बीच बने असामान्य कनेक्शन को अलग करना पड़ता है। साथ ही कम वजन और संक्रमण का खतरा भी सर्जरी को और चुनौतीपूर्ण बना देता है।

बच्चे के पिता कल्पेशभाई ने बताया कि डॉक्टरों ने पूरी स्थिति समझाते हुए बताया था कि ऑपरेशन जोखिम भरा है, लेकिन यही एकमात्र विकल्प है जिससे बच्चे की जान बचाई जा सकती है। इसके बाद विशेषज्ञ सर्जिकल टीम ने पूरी सावधानी और कुशलता के साथ ऑपरेशन किया और सफलतापूर्वक ट्रेकियो-इसोफेगल फिस्टुला को अलग कर दिया।

सर्जरी के बाद बच्चे को करीब 10 दिनों तक मैकेनिकल वेंटिलेटर पर रखा गया, ताकि उसकी सांस और शरीर की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों को स्थिर रखा जा सके। इस दौरान डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने लगातार उसकी निगरानी की। संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए गए और नवजात की विशेष देखभाल की गई।

इलाज के दौरान डॉक्टरों ने 'डाई स्टडी' नामक जांच भी की, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि सर्जरी के बाद भोजन नली सही तरीके से काम कर रही है। इस जांच में पुष्टि हुई कि अब दूध सही रास्ते से सीधे पेट में जा रहा है और सांस की नली में जाने का खतरा नहीं रहा। यह रिपोर्ट डॉक्टरों के लिए राहत भरी साबित हुई।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार निजी अस्पतालों में इस तरह की एनआईसीयू सर्जरी और इलाज का खर्च प्रतिदिन लगभग 20 से 25 हजार रुपये तक हो सकता है। इसके अलावा जटिल ऑपरेशन और लंबे समय तक गहन देखभाल का खर्च लाखों रुपये तक पहुंच जाता है। लेकिन एसएसजी अस्पताल में यह पूरी सर्जरी और 24 दिनों तक चला गहन उपचार पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया गया।

अस्पताल प्रशासन ने न केवल बच्चे का इलाज किया बल्कि उसकी मां के रहने और भोजन की व्यवस्था भी अस्पताल परिसर में ही की गई, ताकि परिवार को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

करीब 24 दिनों तक एनआईसीयू में इलाज और निगरानी के बाद बच्चे की स्थिति पूरी तरह स्थिर हो गई। डॉक्टरों के अनुसार अब वह स्वस्थ है, सामान्य रूप से सांस ले रहा है और मां का दूध भी पी रहा है। स्वास्थ्य में सुधार और वजन बढ़ने के बाद डॉक्टरों ने उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी।

इस सफल सर्जरी का नेतृत्व अस्पताल के पीडियाट्रिक्स विभाग के प्रमुख Omprakash Shukla के मार्गदर्शन में किया गया। इस ऑपरेशन में डॉ. रिंकी शाह, डॉ. वैशाली चनपुरा, डॉ. कश्यप पंड्या, डॉ. रवीश, डॉ. अनन्या और डॉ. रचना सहित सर्जिकल और पीडियाट्रिक विशेषज्ञों की टीम शामिल थी, जिन्होंने समन्वय और विशेषज्ञता के साथ इस जटिल सर्जरी को सफल बनाया।

डॉक्टरों का कहना है कि समय पर सही इलाज और टीमवर्क की बदौलत ही बच्चे की जान बचाई जा सकी। अस्पताल की यह उपलब्धि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता, विशेषज्ञता और समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जा रही है। यह घटना यह भी दर्शाती है कि सरकारी अस्पतालों में भी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और कुशल डॉक्टर मौजूद हैं, जो गंभीर से गंभीर मामलों में भी मरीजों को नई जिंदगी दे सकते हैं।

सत्यमेव जयते
गुजरात सरकार

समान अवसर और समरसता के माध्यम से विकसित गुजरात का निर्माण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए कुल ₹7,086 करोड़ का प्रावधान

- प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति तथा विकसती जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं गणवेश सहायता प्रदान करने हेतु **₹617 करोड़** का आवंटन
- आवास योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को मकान सहायता देने के लिए **₹375 करोड़** का प्रावधान
- संत सूरदास योजना तथा विभिन्न आर्थिक सहायता योजनाओं के अंतर्गत कुल **₹249 करोड़** का प्रावधान
- विदेश अध्ययन ऋण योजना के अंतर्गत 4% ब्याज दर पर प्रति व्यक्ति ₹15 लाख तक का ऋण प्रदान करने हेतु **₹135 करोड़** का आवंटन
- निःशुल्क (पोषण) चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत **₹143 करोड़** का प्रावधान
- अनुसूचित जाति के लगभग 1 लाख 45 हजार विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु **₹296 करोड़** का आवंटन

विकसित भारत
गुजरात बजट 2026-27
विकसित गुजरात

"समाज के हर वर्ग का सम्मान, शिक्षा और आर्थिक उत्कर्ष ही हमारी सरकार का मूल मंत्र है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का यह बजट सामाजिक पंक्ति में
अंतिम व्यक्ति को सशक्त कर, 'समरस और विकसित गुजरात' के निर्माण को नई गति देगा।"
- श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात